

विहगावलोकन

समष्टि-वित्तीय जोखिम

वैश्विक वृद्धि की वर्तमान कमजोर संभावना के कारण अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं(एई)में मौद्रिक नीति का सुगम रुझान जारी रह सकता है। परिणामस्वरूप, जोखिम के प्रतिफल कम होने से कमजोरी बढ़ सकती है और बाजारों में अचानक तेजी से होने वाले उछाल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी तक, वित्तीय जोखिम लेने का सहगामी असर आर्थिक जोखिम लेने पर नहीं पड़ा है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं(एई) में ब्याज दरें निम्न स्तर पर होने की पृष्ठभूमि के साथ उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में पोर्टफोलियो प्रवाह मजबूत रहा है जिससे उसकी (पोर्टफोलियो) वापसी का जोखिम बढ़ गया है जिसका वृद्धि पर विपरीत असर पड़ने अथवा वित्तीय बाजार जोखिमों की संभावना बढ़ गई है। इस प्रकार से, और अधिक सतर्कता जरूरी हो गई है।

घरेलू मोर्चे पर, हाल के महीनों में वृद्धि की संभाना में सुधार होने, मुद्रास्फीति में गिरावट आने, विदेशी क्षेत्र में सुधार होने तथा राजनीतिक स्थिरता के साथ समष्टि आर्थिक कमजोरियों में काफी कमी आई है। हालांकि, निवेश के इरादों के कमजोर होने के कारण बैंकिंग कारोबार की वृद्धि तथा प्राथमिक पूंजी बाजारों में वृद्धि कमजोर बनी हुई है। वास्तविक परिणामों में, कारोबारी मनोभावों को बरकरार रखने की अनिश्चितता बनी हुई है।

वित्तीय संस्थाएं : गतिविधियां एवं स्थिरता

2013-14 के दौरान भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की वृद्धि में और अधिक गिरावट आई है। बैंकों के बकाया ऋणों के लिए प्रावधानीकरण के उच्च स्तर तथा ऋण की मंद वृद्धि होने के कारण लाभप्रदता में कमी आई। शहरी एवं ग्रामीण सहकारी बैंकों के वित्तीय हालात से प्रमुख सूचकों की भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों का पता चलता है। शहरी सहकारी बैंकों ने बेहतर प्रदर्शन किया किंतु प्राथमिक कृषि ऋण समितियों तथा दीर्घावधि ग्रामीण ऋण समितियों का कार्य निष्पादन उनकी हानियों के साथ ही आस्ति गुणवत्ता में गिरावट होने के कारण चिंता का विषय बना हुआ है। जमा स्वीकार नहीं करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों(प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण) की आस्ति के

आकार में वृद्धि देखी गई किंतु समीक्षा अवधि में उनकी आस्ति गुणवत्ता में और अधिक गिरावट आ गई है।

बैंकिंग स्थिरता सूचक से पता चलता है कि 2014-15 की पहली छमाही के दौरान बैंकिंग क्षेत्र पर समग्र जोखिम अपरिवर्तित रहा। व्यक्तिशः आयामों के अंतर्गत, प्रणाली में चलनिधि की स्थिति में सुधार हुआ है किंतु सुदृढ़ता में कमी होने के साथ ही आस्ति गुणवत्ता में गिरावट होने के कारण चिंताएं बनी हुई हैं। सूचक के लाभप्रदता आयाम में सुधार का पता चलता है किंतु यह अभी भी धीमा बना हुआ है। दबाव परीक्षण से पता चलता है कि समष्टि आर्थिक परिस्थितियों में संभावित सकारात्मक गतिविधियों के तहत बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में आने वाले समय में सुधार हो सकता है और बैंक अपने वर्तमान प्रावधान के स्तर के साथ संभावित हानियों को पूरा करने की स्थिति में हो सकते हैं। हालांकि, यदि समष्टि आर्थिक परिस्थितियां बहुत अधिक खराब हो जाएं तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में वर्तमान स्तर से और गिरावट आ सकती है और बैंक, प्रतिकूल समष्टि आर्थिक जोखिम परिदृश्यों के अंतर्गत पर्याप्त प्रावधान के रूप में प्रत्याशित हानियों को पूरा करने में पीछे रह सकते हैं।

परस्पर संबद्धता के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों की तुलना में अंतर-बैंक बाजार का आकार धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। किंतु, पाँच अत्यधिक संबद्ध बैंकों के संक्रामक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि यदि कोई एक बैंक संक्रामकता का शिकार होता है तो संयुक्त ऋण-शोधन-चलनिधि स्थिति के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली अपनी टियर-1 पूंजी का काफी हिस्सा गंवा सकती है।

वित्तीय क्षेत्र विनियमन और मूलभूत सुविधाएं

जहां वाणिज्यिक बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) सितंबर 2014 में 12.8 प्रतिशत पर संतोषजनक है, वहीं आगे चलकर बैंकिंग क्षेत्र, विशेषकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए अतिरिक्त पूंजी बफर के संबंध में विनियामकीय अपेक्षा को पूरा करने के लिए और अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी।

विनियामक द्वारा, जानबूझकर की गई चूक के मामलों को अलग-अलग करके देखने पर अधिक ध्यान देने तथा होने वाली चूक के नुकसान में प्रवर्तकों की समान सहभागिता सुनिश्चित करने को देखते हुए इस बात की आवश्यकता है कि निवल आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन और बड़े कॉर्पोरेट ऋण पुनर्चना(सीडीआर) के मामलों की प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाई जाए। इससे जुड़ा एक अन्य पहलू है जो बैंकों की आस्ति गुणवत्ता को चुभता है वह है कॉर्पोरेट लीवरेज और बैंक के तुलनपत्रों पर उसके मूल्यांकन का प्रभाव, खासतौर से होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर द्वारा 'दुगुनी लीवरेजिंग' तथा प्रवर्तकों द्वारा शेयरों को गिरवी रखना है।

भारतीय स्टॉक बाजार ने हाल के महीने में तेजी से प्रगति की है। जहां उसमें खुदरा निवेशकों का आधार अभी भी अपेक्षाकृत कम रहा है, वहीं भारत के स्टॉक बाजार ने भारी मात्रा में विदेशी निवेश को आकर्षित किया है, किंतु विभिन्न युक्तियुक्त कारणों से उसकी

वापसी का जोखिम बढ़ गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने प्रमुख निपटान गारंटी निधि के रूप में एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच बनाया है जिससे व्यापार के निपटान में संभावित चूक के जोखिम को समाप्त किया जा सके और घरेलू पूंजी बाजार में जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत किया जा सके।

वास्तविक उपयोगकर्ताओं/हेजर्स की सहभागिता बढ़े और बाजार में मूल्य-निर्धारण की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) ने पोजीशन लिमिट को संशोधित किया है जो अंतर्निहित पण्यों के उत्पादन तथा आयात के अनुमानों से संबद्ध होती हैं।

अनधिकृत रूप से जमाराशियां स्वीकार करने एवं वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित मामलों से निपटने के लिए वित्तीय स्थिरता और विकास संघ (एफएसडीसी) की पहल के अंतर्गत राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) को और मजबूत बनाया गया है।